

बजट अनुमान 2002-2003

वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 45,873 करोड़ रुपए की वृद्धि दिखाई देती है, आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि 31,527 करोड़ रुपए है जबकि आयोजना के अधीन 14,346 करोड़ रुपए है जिसमें से 7,751 करोड़ रुपए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आयोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता और 6,595 करोड़ रुपए केंद्रीय आयोजनाओं पर व्यय के लिए है। आयोजना-भिन्न अनुमानों में मुख्य मदों की घट-बढ़ को नीचे सारणी में दिया गया है:-

	(करोड़ रुपए)		
	संशोधित 2001-02	बजट 2002-03	घट-बढ़
आयोजना-भिन्न			
1. ब्याज संदाय	107257	117390	(+ 10133)
2. रक्षा	57000	65000	(+ 8000)
3. खाद्य सब्सिडी	17612	21200	(+ 3588)
4. उर्वरक सब्सिडी	11944	11228	(-) 716
5. पेट्रोलियम सब्सिडी	...	6495	(+ 6495)
6. पुलिस	7305	8352	(+ 1047)
7. राज्य सरकारों को अनुदान	16306	18524	(+ 2218)
8. पेंशन	14628	15035	(+ 407)
9. शिक्षा	2381	2728	(+ 347)
10. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	30849	30857	(+ 8)
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय	265282	296809	31527

1. यह वृद्धि सरकारी व्यय के वित्तपोषण के लिए ऋण संसाधनों पर बनी हुई निर्भरता के कारण है। वृद्धिकारी व्यय की आवश्यकता मुख्यतः वर्ष 2001-2002 के दौरान राजकोषीय घाटे की ब्याज देयताओं को पूरा करने के लिए है।
2. बढ़ी हुई यह व्यवस्था रक्षा बलों के वेतन और भत्तों तथा आधुनिकीकरण पर वर्धित व्यय को पूरा करने के लिए है।
3. भारतीय खाद्य निगम के पास भारी स्टाक के कारण उच्च पिछली लागत के कारण है।
4. सब्सिडी में कमी मूल्यों में समायोजन के कारण है।
5. नियंत्रित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने से घरेलू एल.पी.जी., सार्वजनिक वितरण प्रणाली मिट्टी तेल, के लिए सब्सिडियों, दूर-दराज के क्षेत्रों के लिए भाड़ा सब्सिडी और अन्य संबंधित प्रतिपूर्ति के लिए पहली बार 2002-03 में प्रावधान किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों को सरकारी बाण्ड जारी करने से 31 मार्च, 2002 को तेल पूल घाटा भी आंशिक रूप से कम हो जाएगा।
6. इस वृद्धि में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामान्य वृद्धि और विशेष कार्य (आपरेशन) शामिल है।
7. यह वृद्धि ग्यारहवें वित्त आयोग की राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदानों की सिफारिशों के आधार पर है।
8. यह वृद्धि मुख्यतः महंगाई राहत और प्रत्याशित सेवानिवृत्तियों के कारण है।
9. यह वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों, केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों आदि के कर्मचारियों के वेतनों में वृद्धि के कारण है।